

Newspaper Clips June 30, 2016

Asian Age ND 30/06/2016

P-02

IIT tests in Saarc, UAE, but not Pak

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, JUNE 29

The prestigious IITs, which will for the first time hold entrance tests abroad including in Saarc nations, will exclude Pakistan for the forthcoming year.

While preparations are underway for conducting entrance tests in Singapore, the UAE and Saarc countries for undergraduate and post-graduate courses, Pakistan will not figure in the list. This newspaper had in February this year first reported that the prestigious IITs are likely to hold their entrance tests in several foreign nations from 2017 to select foreign students for undergraduate and post-graduate courses.

“Considering various factors, especially difficulties involved with regard to students procuring visas, it has been decided that entrance tests for IITs may not be conducted in Pakistan for the upcoming year,” sources said.

Officials said seats for foreign nationals would be additional in nature and

would not reduce those available to Indians at these institutes. The decision was taken after consultations between officials of the Union human resources development and external affairs ministries, sources added.

“The entrance tests to the IITs abroad have been held till now only to admit Indian nationals. This is for the first time that it has been planned to admit foreign students through tests held abroad. It is aimed that the plan would be operationalised from the JEE/GATE exams to be conducted in 2017,” sources said.

Students will be selected through a common entrance exam which would be administered by the IIT with the help of Indian missions in these countries. The fee applicable in the case of foreign students will also be more as the subsidised fee, which Indians pay, would not be applicable to them.

Meanwhile, the Union Cabinet on Wednesday approved revised cost estimates for eight new IITs.

Cabinet approves ₹13,990-cr revised cost estimate for eight new IITs

OUR BUREAU

New Delhi, June 29

The setting up of eight new Indian Institutes of Technology (IIT) will now cost an estimated ₹13,990 crore as against ₹6,080 crore, after the Cabinet approved the revised cost estimates on Wednesday.

The initial cost estimate was over a period of 11 years from 2008-09 till 2018-19 and an official statement said that the increase in expenditure was due to the escalation in time and cost overruns. The new IITs will come up in Bhubaneswar, Gandhinagar, Hyderabad, Indore, Jodhpur, Mandi, Patna and Ropar. The student strength at each IIT at the end of the project will be 2,360, the statement added. Further, the total student capacity in the eight IITs will be 12,880 by March 2019.

"Indirectly, the eight new IITs would be expected to bring about quantitative and quality growth in areas of research, publication of books and research paper-

s. These institutes would also meet the emerging needs of the industry and the economy as a whole," the statement added.

Further, the Cabinet also gave an ex-post-facto approval for extension of Addendum IX from April 1, 2011 till March 31, 2016 and renewal of the Memorandum of Understanding between the Government of India and Shastri Indo-Canadian Institute (SICI) for five years by way of signing a supplementary Addendum X to the MoU first signed in 1968.

Under Addendum X, the Ministry of Human Resource Development has approved an expenditure of ₹33,176 crore for the period from April 1, 2016 till March 31, 2021 or the entire five-year period.

The Cabinet also approved the signing of an MoU between India and Tanzania for bilateral cooperation in water resources management and development. The signing of an MoU between the Union Public Service Commission and the Royal Civil Service Commission of Bhutan was also approved.

Hari Bhumi ND 30/06/2016 P-14

आईआईटी संस्थानों की निर्माण लागत में बढ़ोतरी पर मुहर

हरिभूमि ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आठ नए आईआईटी संस्थानों के स्थायी कैम्पस निर्माण के लिए संशोधित लागत राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 13 हजार 990 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इस बाबत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2008-09 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने आठ नए आईआईटी संस्थानों के मठन को मंजूरी दी थी।

इसमें आईआईटी इंदौर, गांधीनगर, रोपड़, पटना, जोधपुर, हैदराबाद, भुवनेश्वर और मंडी शामिल थे। उस वक्त इनके लिए 6 हजार 80 करोड़ रुपये की निर्माण लागत

रखी गई थी। इसमें प्रत्येक आईआईटी के लिए 760 करोड़ रुपये निर्माण लागत तय की गई। कैबिनेट ने अपनी बैठक में कहा कि पिछली सरकार ने निर्माण लागत का निर्धारण वर्ष 2006 के मूल्य सूचकांक (इंडेक्स रेट) के हिसाब से बिना साइट का सर्वे किए हुए तय किया था। लेकिन अब मौजूदा दौर में इसमें काफी बदलाव हो चुके हैं। प्रत्येक आईआईटी

■ आठ नए संस्थानों की संशोधित निर्माण लागत का था प्रस्ताव

संस्थान में 10 हजार छात्र पढ़ते हैं। इसके कैम्पस के निर्माण के लिए 50 लाख स्क्वायर फीट जगह को जल्दतः पड़ती है।

स्थायी कैम्पस का निर्माण होगा

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई संशोधित धनराशि के तहत इंजीनियरिंग के इन प्रतिष्ठित संस्थानों के स्थायी कैम्पस का निर्माण होगा। इसमें आईआईटी इंदौर के लिए 1 हजार 902 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। पहले यह धनराशि 760 करोड़ रुपये थी। आईआईटी रोपड़ के लिए 1 हजार 668 करोड़ रुपये, गांधीनगर के लिए 1 हजार 716 करोड़ रुपये, पटना के लिए 1 हजार 678 करोड़ रुपये, भुवनेश्वर के लिए 1 हजार 880 करोड़ रुपये, मंडी के लिए 1 हजार 466, हैदराबाद के लिए 2 हजार 75 करोड़ रुपये, जोधपुर के लिए 1 हजार 605 करोड़ रुपये का प्रावधान संशोधित धनराशि में किया गया है।



Amar Ujala ND 30/06/2016
P-11

गरीब और दिव्यांग छात्रों को फीस माफी का तोहफा जल्द

नई दिल्ली (ब्यूरो)। आईआईटी, एनआईटी में आर्थिक रूप से पिछड़े व दिव्यांगों को फीस माफी के बाद अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि पूरे देश के किसी अन्य दिक्कत के चलते होनहार छात्र उच्च शिक्षा से दूर न हों। यह कहना है मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का।

स्मृति ईरानी बुधवार को एक काम देश के नाम संस्था द्वारा आयोजित नरेंद्र मोदी ऐप से जुड़ने के संकल्प कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित कर रही थीं। मंत्री ने कहा देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक लाख से कम आय वाले परिवारों के छात्रों को पूरी फीस माफ और पांच लाख तक आय वाले परिवारों के छात्रों को राहत देने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा अब छात्र यदि दाखिला लेने के 20 दिन के बाद कॉलेज बदलना चाहते हैं तो भी उनकी फीस में से कुछ राशि काटने के बाद अन्य वापस कर दी जाएगी। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि ऐप से प्रधानमंत्री को जानने के साथ-साथ वे शिक्षा के संबंध में सुझाव भी भेजें।

कार्यक्रम में मोदी ऐप प्रयोग करने वाले युवाओं से कहा कि आप जैसे युवाओं के चलते एक चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री है। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो सोचते हैं

● मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की युवाओं से अपील



आठ आईआईटी के फंड को दोगुना करने की मंजूरी

नई दिल्ली (ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2008-09 में स्थापित आठ आईआईटी के फंड को दोगुना करने की मंजूरी दे दी है। आईआईटी मंडी, रोपड़, गांधी नगर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर और पटना को खुले तो पांच वर्ष से अधिक हो गए लेकिन सुविधाओं की कमी के चलते छात्र दाखिला लेने में आनाकानी करते थे। पहले इन आठ आईआईटी को 6080 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत था, जोकि अब 13,990 करोड़ रुपये हो गया है।

कि सत्ता सिर्फ उनकी जागीर है। यहां मौजूद युवा किसी पार्टी कार्यालय के बाहर टिकट के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रधानमंत्री से ऐप के माध्यम से सीधी बात करने के लिए पहुंचे हैं। बिहार के शिक्षामंत्री अशोक चौधरी से विवाद का किस्सा कार्यक्रम में स्मृति ने छोड़ दिया।

GATE heads abroad, first time in 2017

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/GATE-heads-abroad-first-time-in-2017/articleshow/52983086.cms>

Chennai: Following in the footsteps of IIT-JEE, which will be conducted abroad in 2017, the Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE), which determines entry to master's and direct PhD courses in IITs and other reputed institutes, is also going overseas for the first time next year. The exam will be conducted in Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Singapore, United Arab Emirates and Ethiopia, confirmed Govind Chakrapani, organising chairman for GATE 2017 from IIT-Roorkee in a press release. He said the move would widen horizons of the academic environment in IITs and other institutes.

IIT-Madras director Bhaskar Ramamurthi said the move would attract more foreign students to the country. "At the last IIT council meeting it was decided that the number of foreign students on campus should get a fillip. Earlier, we had the DASA (Direct Admissions for Students Abroad) programme. But that was scrapped since we weren't happy with the quality of students coming in," he told TOI. "The seats that will be created are only supplementary or additional in nature. Our students' seats won't be taken away.

If the number of foreign students and faculty helps us climb in international rankings, it is a good step. But this is not the main mandate of the council as far as inducting foreign students is concerned," he said. MV Reddy, president of coaching institute Time, said it would bode well for the international rankings of the country's institutes by boosting the diversity factor. GATE 2017 is scheduled for February 4-5 and 11-12, 2017. Online registrations begin on September 1 and end on October 4. Change of examination centre will be entertained till November 16 while admit cards can be downloaded from January 5, 2017.

IIT-Roorkee has set March 27, 2017 as the date for declaration of results.

Amar Ujala ND 30/06/2016 P-11

पीपीओ पाने वाले छात्रों का अब कैंपस सेलेक्शन नहीं

कानपुर (ब्यूरो)। आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद इंटरनेशनल और प्री प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) पाने वाले छात्रों को अब कैंपस सेलेक्शन से दूर रखा जाएगा। यह व्यवस्था सत्र 2016-17 से लागू होगी। आईआईटी प्रशासन का कहना है कि प्री प्लेसमेंट एक तरह से जॉब ऑफर है। दोबारा मौका देने का कोई औचित्य नहीं है।

आईआईटी से बीटेक, बीएस, एमटेक, एमएससी, पीएचडी और एमडैस करने वाले 150 स्टूडेंटों को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है। फेसबुक ने भी पांच छात्रों को प्री प्लेसमेंट दे दिया है। यह प्रक्रिया अगस्त 2016 तक चलती रहेगी। इससे पहले ही पीपीओ की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया। कहा गया कि अब प्री प्लेसमेंट पाने वाले छात्रों को कैंपस सेलेक्शन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। पूर्व में कई छात्रों को पीपीओ मिला था, लेकिन उनके प्लेसमेंट प्रक्रिया

नौ फीसदी छात्र लेंगे उच्च शिक्षा

नौ फीसदी आईआईटीयंस ने उच्च शिक्षा (एमटेक, एमएससी, एमडैस, एमबीए या फिर एमएस) और रिसर्च (पीएचडी) में जाने का फैसला किया है। ज्यादातर छात्र अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से पीएचडी करने जा रहे हैं।

फिलपकार्ट देगी तैनाती

ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फिलपकार्ट ने भले ही कैंपस सेलेक्शन के बाद आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य आईआईटी के छात्रों को जॉइनिंग नहीं दी लेकिन आईआईटी कानपुर से सेलेक्ट सात छात्रों का जॉब ऑफर जस का तस है। जल्द ही सबको अच्छे वेतन पर तैनाती मिल जाएगी।

में हिस्सा लेने के कारण तमाम अन्य छात्रों का काफी हद तक नुकसान भी हुआ था।



सत्र 2016-17 से पीपीओ की प्रक्रिया बदली गई है। आईआईटी कानपुर का कैंपस सेलेक्शन इस बार शानदार है। 91 फीसदी छात्रों का प्लेसमेंट हुआ। 9 फीसदी छात्र उच्च शिक्षा में गए। इस हिसाब से देखा जाए तो सेलेक्शन 100 फीसदी है। इसका ब्योरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जा चुका है। - प्रो. दीपू फिलिप, प्लेसमेंट अधिकारी आईआईटी कानपुर

आईआईटी इंदौर का नया कैंपस विद्यार्थियों के लिए बना मुसीबत प्रदूषण के बीच 8 घंटे कर रहे शोध, बीमार हो रहे विद्यार्थी

इंदौर। अक्षय बाजपेयी

आईआईटी का नया कैंपस विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बन गया है। प्रदूषण के बीच पढ़ाई, शोध करने के कारण विद्यार्थी एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। यही नहीं छात्रों ने जब शिकायत डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर से की तो उन्होंने इसकी चर्चा किसी से नहीं करने और शोधार्थियों को ग्रांट रोकने की धमकी दे डाली।

आईआईटी प्रबंधन ने सिमरौल स्थित नया कैंपस पूरा तैयार किए बिना ही यहां विद्यार्थियों को भेज दिया। नतीजा यह है कि दिनभर धूल के गुबार के बीच विद्यार्थियों को पढ़ाई करना पड़ रही है। करोड़ों रुपये की मशीनें निर्माणधीन इमारत में रख दी गईं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्यूटर साइंस की लैब में निर्माण कार्य चल रहा है। विद्यार्थी मास्क पहनकर शोध करने को मजबूर हैं।

30 इमारतों में से आधी भी तैयार नहीं : शहर से 25 किमी दूर इस कैंपस में करीब 30 इमारतें बनना हैं। हालात ऐसे हैं कि आधी इमारतें भी पूरी नहीं हो सकीं। (पीएससीएल) व आईआईटी स्थित कैंपस को आईआईटी प्रबंधन पहले ही खाली कर चुका है। नए



इंदौर आईआईटी परिसर में चल रहा निर्माण कार्य। जो छात्रों के लिए बना मुसीबत।



धूल से भरा रहता है पूरा परिसर।

सभी की परेशानी

कैंपस में निर्माण चल रहा है। इससे कुछ परेशानियां सभी के लिए हैं। एचआरए बंद करने का निर्णय नियमों के तहत लिया गया है। आईआईटी व पीएससीएल में खर्चा ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमें नए कैंपस में शिफ्टिंग जल्द से जल्द करना था। कुछ दिनों में समस्याएं खत्म हो जाएंगी।

- डॉ. निर्मला मेनन, प्रोफेसर, आईआईटी, इंदौर

कैंपस की हालत इतनी खराब है कि अभी तक सड़कें भी तैयार नहीं हुईं। बिना बस के विद्यार्थी इधर से उधर जा भी नहीं सकते। लैब में विद्यार्थियों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा।

अगस्त से एचआरए कर दिया जाएगा बंद : आईआईटी के फैकल्टी,

पीएचडी स्कॉलर्स व विद्यार्थी अभी बायपास स्थित सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप में रह रहे हैं। पीएचडी स्कॉलर्स को हर माह 25 हजार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। इसमें से 5 प्रतिशत यानी 5 हजार रुपये प्रतिमाह हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) दिया जा रहा था, लेकिन आईआईटी प्रबंधन अगस्त से स्कॉलर्स को एचआरए नहीं देने का फरमान जारी कर चुका है। इसे लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश है।

पीआरओ से बात करिए

मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। हमारे यहां पीआरओ ही जानकार देते हैं। आप उनसे बात करिए।

- डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव, डीन स्टूडेंट वेलफेयर

आईआईटी के बजट में ढाई गुना का इजाफा

इंदौर। आईआईटी के विकास बजट में ढाई गुना का इजाफा किया गया है। केंद्र सरकार ने इस बार 1902 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार ने 2008-09 में स्थापित 8 आईआईटी के विकास के लिए 13 हजार 990 करोड़ रुपये की बजट राशि मंजूर की। सबसे ज्यादा राशि हैदराबाद को 2075 करोड़ और आईआईटी इंदौर को ज्यादा राशि मिली है। सन् 2009 में शुरू हुए आईआईटी इंदौर कैंपस का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हो पाया है।

JNU Vice Chancellor Mamidala Jagadesh Kumar appointed UGC member

<http://www.indiatvnews.com/news/india-jnu-vice-chancellor-mamidala-jagadesh-kumar-appointed-ugc-member-337136>

New Delhi: The Ministry of Human Resource Development has appointed Jawaharlal Nehru University (JNU) Vice Chancellor Mamidala Jagadesh Kumar as a member of the University Grants Commission (UGC).

IIT Delhi professor M Jagdeesh Kumar was appointed as the Vice Chancellor of the JNU earlier in January. His name was cleared by President Pranab Mukherjee from a panel of four names that were forwarded to him by the HRD ministry.

A professor of electrical engineering at IIT Delhi, Kumar worked for strengthening collaboration between institutions, streamline recruitment process and interaction with students.

Kumar, a karate expert, was born in Mamidala, Nalgonda district, Andhra Pradesh.

He was also the organising chairman of Graduate Aptitude Test in Engineering GATE, 2012, with the overall responsibility of organising the test across India in 860 centers spread over 170 cities and towns.

Kumar had recently faced criticism after he reportedly attended an RSS linked event. He had, however, denied having any formal association with any organisation include the Sangh.

Aaj Samaj ND 30.06.2016 P-08

केन्द्र सरकार ने निभाया अपना वादा : धूमल

□ आईआईटी मंडी को मिला राष्ट्रीय स्तर का दर्जा, बजट भी दो गुणा : प्रो. धूमल

आज समाज नेटवर्क
 शिमला। केन्द्र की एनडीए सरकार ने अपना वादा निभाते हुए आईआईटी मंडी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया है और इसके निर्माण के लिए बजट में बढ़ोतरी करते हुए दो गुना कर दी है। यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने बुधवार को यहां जारी वक्तव्य में दी। उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी का कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ था और उस समय इसका प्रस्तावित बजट 760 करोड़ रुपये था, परंतु वृषीए सरकार द्वारा बजट का सही आंकलन नहीं होने की वजह से विस्तारीकरण की योजनाओं में धन की भारी कमी आड़े आ रही थी, जिसकी वजह से संस्थान के निर्माण कार्य रुके हुए थे। उन्होंने बताया कि आज मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दूरभाष के माध्यम से उन्हें स्वयं अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मामले का संज्ञान लेते हुए आईआईटी मंडी को विशेष शिक्षण संस्थान व राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देते हुए बजट 760 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1466 करोड़ रुपये कर दिया है और यह बजट पूर्व की तुलना में लगभग दो गुना है। इससे आने वाले समय में यह संस्थान राष्ट्र के प्रमुख आईआईटीज में शामिल हो जाएगा। प्रदेश के प्रति इस विशेष उपहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी बधाई की पात्र हैं और प्रदेश की जनता उन्हें हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती है।

LEARNING CURVE

Government seeks comments on its inputs to education policy

BY GYAN VARMA & ANUJA

NEW DELHI

Revision of no-detention policy, promotion of Sanskrit, and bringing back Class X board examinations are some of the key changes that the central government may include in its new education policy, the human resource development ministry said on Wednesday.

The HRD ministry released a 43-page document detailing several inputs for the new policy due after a gap of three decades on the www.mygov.in website.

The document also focuses on addressing gender discrimination, creation of educational tribunals and a common curriculum for science, mathematics and English.

The education policy aims to ensure "quality education and lifelong learning opportunities".

On the face of it, the release seems to be the HRD ministry's inputs to the committee drafting the education policy. It does not appear to be a summary of the over 200-page report submitted by a five-member committee, headed by former cabinet secretary T.S.R. Subramanian, who said he would respond only after seeing the release.

The committee submitted its report to the government last month. The new education policy, India's first in three decades, is expected to address various critical issues in the education sector, which, while it has grown in scale and complexity, suffers from several problems related to quality and relevance.



Seeking feedback: Union HRD minister Smriti Irani.

Earlier this month, a controversy broke out over the new policy when Subramanian wrote to the HRD ministry, urging it to make the report public, and threatened to do so himself. Union HRD minister Smriti Irani had then responded saying she would not release the report without feedback from the states and that she did not want to make it "the legacy of one individual".

Under the "policy framework" head, the inputs list 21 pointers, including pre-school education, curriculum renewal, school assessment, quality assurance, internationalization, faculty development in higher education, and language and culture in education.

The release also recommends a five-year review of the policy to "keep up with the emerging national and global trends". It also sets the target of at least 90% of the adult population meeting literacy and numeracy skills prescribed by adult education programmes.

The main objective of the draft policy, the release says, is to ensure that all preschoolers (children between the ages of 4 and 5) attain the learning and developmental readiness required for smooth transition to primary education. The policy also aims to achieve universal elementary and secondary education and ensure that anyone who clears the secondary level has access to higher secondary education.

With the aim to make education accessible, inclusive and responsive to the needs of diverse groups of children and young people, the release talks about special focus on students from disadvantaged population groups.

It seeks to eliminate social, regional and gender gaps in education.

The document also stresses the need to reform the higher education system to ensure equitable access to tertiary education, including technical and professional education, end inequalities in access to higher education, and improve teaching and research, promote innovation and generate new knowledge across all higher education institutions.

gyan.v@livemint.com

Draft policy opens the door for foreign universities

CBSE Class X boards to be made mandatory; Indian Education Service mooted

By Business Line
New Delhi, June 29

The government on Wednesday invited public comments on the revision that the Ministry of Human Resource Development aims to take under its much-awaited New Education Policy. It has updated the Draft National Education - Policy proposal through its citizen engagement platform MyGovIndia and the last date for inputs from the people is July 9.

The process involves setting up an Education Commission every five years, creation of an Indian Education Service, Central Educational Statistics Agency and reconstituting the National Council of Educational Research and Training, apart from possible for a foreign university to offer its own degree to the Indian students studying in India.

While MyGovIndia has updated a 49-page draft "Some inputs for Draft New Education Policy", the CSR Subramanian-led com-

mittee set up to formulate the policy had submitted a 230-page report to the Ministry.

Foreign universities

Aiming for internationalisation of education, select foreign universities, from the top 100 in the world, will be encouraged to set up shops in India in collaboration with Indian institutions.

"If required, steps will be taken to put in place an enabling legislative, policy regulations will be framed so that it is possible for a foreign university to offer its own degree to Indian students studying in India, such that their degrees will be valid also in the country of origin," it said, adding that Indian institutions will also be allowed to set up campuses abroad. If required, through suitable legislation or amendments in the relevant Acts or statutes.

Higher education

According to the draft, "An Education Commission comprising



In global education in the country, foreign universities from the top 100 will be encouraged to set up campuses.

academic experts will be set up every five years to assist the Ministry in identifying new knowledge areas, disciplines and domains as well as pedagogic, curricular and assessment reforms at the global level."

The government will endeavour to implement the recommendations of the earlier policies of 1986 and 1992/93 for the creation

of an Indian Education Service (IES), indicated in the current proposals too, the draft notes.

The IES will be an all India service with the MHRD as the cadre controlling authority. Till the IES comes into existence, an interim step of a one-time special recruitment by CPSC from among the existing academic and administrative positions in the education

service in various States will be made, in concurrence with the States.

Moreover, the policy suggests the creation of a Central Educational Statistics Agency for central data collection, compilation and consolidation, with high quality statistical expertise and a management information system that will be used for periodic

analysis, manpower planning and course correction.

An autonomous body, responsible for the promotion, coordination, regulation and maintenance of standards in the Open and Distance Learning/Negative Open Online Courses system, will be set up.

School education

While the National Council of Educational Research and Training (NCERT) will undergo a re-orientation, it will be mandatory for school students to take the Set 2 board examination conducted by the Central and State Boards of Education to which their school is affiliated.

Skill development programmes in schools and as part of the higher education system will be increased not only for gainful employment of students but also to help them develop entrepreneurial skills.

Moreover, transparent and merit-based norms and guidelines for recruitment of teachers will be formulated in consultation with the State governments, the draft says.

IIM-A to get 12 more Research Chairs

Gets commitments worth ₹35 crore for a total of 15 Chairs

RUTAM VORA

Ahmedabad, June 29

Trying to blend focused research with course development, practice and policy, the Indian Institute of Management-Ahmedabad has identified a total of 15 Chairs in areas such as leadership, strategic management and societal development.

While three of them have already been announced, the Institute plans to announce 12 more soon, informed IIM-A Director Ashish Nanda.

The three Chairs already in place at the premier institute include the Nabard Chair in Agri-business, the RBI Chair in Finance and Economics, and the JSW Chair in Innovation and Public Policy.

"We had announced the first chair in October last year. We hope to announce a few more chairs in the coming days as we have already received commitments from

List of Chairs committed at IIM-A

- Infosys Chair in Social Innovation
- Chandrika Tandon Chair in Leadership
- CRISIL Chair in Financial Markets
- ICICI Bank Chair in Strategic Management
- Kasturbhai Lalbhai Chair in Management
- Prof MN Vora Chair in Marketing and Entrepreneurship
- SAP Chair in Social Innovation
- PwC Chair in Financial Reporting and Corporate Governance
- Infosys Foundation Chair in Societal Development

several top institutions and donors," Nanda told *BusinessLine*.

A total of around ₹35 crore has been committed by the likes of Infosys, ICICI

Bank, Kasturbhai Lalbhai, PriceWaterhouseCoopers and Edelweiss, among others.

"The chairs are meant to honour our faculty who are doing cutting-edge work. The cutting-edge work at practice-oriented institutions like IIM-A is different from what is narrowly defined as cutting-edge research - found in most non practice-oriented universities," Nanda said.

He said the assignment of the Chairs is considered based on three aspects. "The first is research; the second teaching and course development, and the third is engagement with practice (industry) and policy," he added.

Currently, the Nabard Chair in agri-business is assigned to the IIM-A faculty Vasant Gandhi; the RBI Chair in Finance and Economics is headed by Abhiman Das;

The JSW Chair in Innovation and Public Policy is headed by economist Rakesh Basant.

President gives nod for dismissal of Pondicherry University V-C

Was served showcase notice after UGC panel found her guilty

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JUNE 29

PRESIDENT PRANAB Mukherjee has given his nod to the Ministry of Human Resource Development's proposal to sack Pondicherry University Vice-Chancellor Chandra Krishnamurthy, who faces charges of plagiarism and misrepresentation.

While Krishnamurthy had submitted her resignation earlier, a ministry official said "the resignation is not valid as it is not addressed to the competent authority, which is the Human Resource Development ministry. The ministry raised objection to her submitting the resignation letter to the President, but she didn't comply. The recommendation to sack her was taken in consultation with the law ministry."

The ministry sent the recommendation for her dismissal on June 26. Ministry officials said with the President clearing her dismissal, Krishnamurthy would not be able to take up a job in any government-run university.

Krishnamurthy was served a showcase notice last August asking why she should not be dismissed after a UGC panel found her guilty of plagiarism and misrepresentation. She was accused of academic fraud amid allegations of holding a fake PhD degree.

She was found to have pla-



The Indian Express reports that were published on (from top) November 22, 2014; August 1, 2015 and May 11, 2016

giarised much of her book, in addition to listing two books in her CV which were never published. Soon after, the ministry appointed Anisa B Khan as the officiating Vice-Chancellor.

This is the second time the Smriti Irani-led HRD ministry has dismissed a Vice-Chancellor of a central university. Earlier, Vijaya Bharati Vice-Chancellor Sushanta Dattagupta was dismissed on charges of financial and administrative irregularities.

Plagiarism to 'academic fraud', her term was mired in controversies

ARUN JANARDHANAN
CHENNAI, JUNE 29

EVER SINCE Chandra Krishnamurthy took charge as Vice-Chancellor of Pondicherry University in November 2012, there was dissent, anger and a series of protests, by both students and faculty.

Her first two years were mired in controversies and allegations. From the reported renovation of the V-C's bungalow at a cost of several lakhs to two gagging victims being punished — the Madras high court later fined the university — and transfer of officials and academics who questioned irregularities.

Among those shunted out was then Registrar Rajeev Vaidyanathi, who was repatriated to his parent department after he sent a number of reports to HRD Minister Smriti Irani on financial irregularities and statutory violations.

A case was also filed in the Madras HC on the violations committed by the then UPA regime in her selection. Documents showed that then HRD Minister P. Raju recommended her name in the file forwarded to the President, although the rules state the ministry has to submit a list of three names in alphabetical order.

Then on November 22, 2014, The Indian Express reported that Krishnamurthy had plagiarised a book mentioned in her CV, which



Chandra Krishnamurthy

listed two other books that had not been published. Over 95 per cent of the book, which was also part of the Mumbai University curriculum, had been copied from papers authored by eminent law scholars, including Padma Shri N R Madhava Menon, founder of National Law School in Bengaluru.

And 24 of Krishnamurthy's 25 research papers and publications listed in her CV — no legal and constitutional studies — did not exist in the UGC database or online repository for law schools.

Her CV was kept away from RTI provisions for several months, under 'protected personal information' category. Later, Vaidyanathi, using his appellate powers on an RTI appeal, made her CV available.

After Vaidyanathi's repatriation, a group of professors of the Pondicherry University Teachers' Association (PUTA) used modern character recognition and plagiarism software to expose the "academic fraud" in her 20-page CV. They also found that her UGC de-

gree was fake, obtained from a fake Sri Lankan University — a finding that was confirmed by an HRD ministry probe panel later.

On Wednesday, Vaidyanathi, currently principal secretary of education in Andaman and Nicobar Islands, said the dismissal was essential to restore the university's academic integrity. While Krishnamurthy was appointed by the UPA regime, she is reported to have enjoyed influence with the NDA administration too.

"Who will compensate for the time and energy we wasted to expose a corrupt V-C? Who will compensate for the number of academic days and research projects we lost in this four-year-long fight, just because the HRD ministry wanted to protect her? Why were both P. Raju and Smriti Irani lenient towards her, despite getting dozens of petitions and official reports on her academic fraud and corruption," asked a faculty member who was attacked on the campus for joining the protests.

It was only in August 2015 that Krishnamurthy agreed to go on leave, on the suggestion of the HRD ministry.

Welcoming the President's decision on Wednesday, Dastagiri Reddy, general secretary of the Pondicherry University Teachers' Association (PUTA), demanded that Krishnamurthy's salary be recovered and charges levied on the perks she enjoyed during her term as V-C.